(b) if so, has any tender been accepted and the details of price, technique and delivery period of the same ;

(c) whether it is a fact that there are indigenous locomotive manufacturers which have not been given any chance, if so, the reasons thereof ; and

(d) how many locomotives were imported during 1980 and what is the requirement of locomotives for 1981 and 1982 ?

THE MINISTER OF COMMERCE & STEEL AND MINES (SHRI PRA-NAB MUKHERJEE) : (a) Yes, Sir.

(b) A Letter of Intent has been placed on M/s. General Electric Company of USA for the supply of 43 medium horse power (600-700 HP) diesel electric locos (including two Nos. required by TISCO) subject to the approval of the Government of India, the base price for each locomotive being US \$ 4,23,100 FOB. The deliveries are scheduled to Commence from June, 1981 at an average rate of one locomotive per week. The locmotives to be supplied are to adopt diesel electric technique. As regards high horse power (1400 HP) diesel electric 'ocomotives, the offers are still under consideration in SAIL.

(c) Railways, who are the main manufactureres of locomotives in the country, had already indicated their inability to meet SAIL'S requirements of medium horse power diesel electric locos upto 1981-82. M/s. JESSOPS and M/s. Suri & Nayyar, who had quoted against the NIT, are not manufacturers of medium horse power locos (600-700 HP) and as such SAIL did not consider them suitable to meet their immediate requirements. However, to encourage the development of indigenous sources of supply, trial orders are under contemplation subject to the settlement of terms and conditions to the satisfaction of SAIL.

(d) No locomotives • were imported during 1980. The like y requirements for 1981 and 1982 are 43 and 29 re-pectively.

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा पूर्तिकर्त्ताओं को ग्रदायगी

1650. श्री मूलचन्द डागा : क्या विरा मंत्रे: यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्योग पूर्तिकर्त्ताओं को समय पर ग्रदायगी नहीं करते हैं; श्रौर (ख) क्या यह भी सच है कि अदायगी में विलम्ब के कारण ब्याज की एक बहुत बड़ी राशि की ग्रदायगी करनी पड़ती है; ग्रौर यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया): (क) और (ख) सरकारी उद्यमों ढारा की गई खरीद के लिए यथासमय भुगतान करने का दायित्व उद्यमों के प्रबन्धकों को सौंपा गया है। किन्तु सरकार इस तर्क को सही नहीं मानती कि अनेक सरकारी उद्यम पूर्तिकर्त्ताओं को समय पर ग्रदायगी नहीं करते और ग्रदायगी में विलम्ब होने के कारण ब्याज की एक बहुत बड़ी राशि की ग्रदायगी करनी पड़ती है।

गुजरात में जी0 क्राई0 क्राई0 सी0 द्वारा प्लेनेटरी मिल प्रोजेक्ट की स्थापना

1651. श्री मोतीभाई ग्रार० औधरी : इस्पात ग्रौर खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने जी० ग्राई० ग्राई० सी० द्वारा प्लेनेटरी मिल प्रोजेक्ट की स्थापना किये जाने की सिफारिश की है; यदि हां, तो यह कब तक स्वीकृत कर दी जायेगी; ; ग्रौर

(ख) क्या स्पंज लौहं ५रियोजना के लिए भो कोई मांग की गई है और यदि हां, तो यह मांग कब तक पूरी कर दी जाएगी?

वाणिज्य तथा इस्पात ग्रौर खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) प्लेनेटरी मिल प्रोजेक्ट की स्थापना करने के लिए मेसर्स गुजरात इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन (जी० ग्राई० ग्राई० सी०) को 17-2-1981 को एक ग्राशय-पत्र जारी किया गया था ।

82

83

(ख) जी, हां । मेसर्स जी० ग्राई० ग्राई० सी० ने गुजरात में स्पंज ग्रायरन का एक कारखाना लगाने हेतु एक ग्रावेदन दिया है । इस समय योजना ग्रायोग तकनीकी-ग्राधिक ग्रध्ययन कर रहा है ग्रौर इसके पूरा हो जाने पर निर्णय ले लिया जाएगा ।

Setting up of Steel Depot in Tripura

1652. SHRI AJOY BISWAS : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to set up a steel depot in Tripura ; and

(b) if so, when it will come up?

THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL & MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) & (b). SAIL are at present examining a proposal of the Tripura State Government for a stock-yard in Dharamnagar. Its opening will depend on land with necessary infrastructural facilities being made availably by the State Government.

Damage to Machinery in Durgapur Steel Plant

1653. SHRI NIREN GHOSH : Will the Minister of STEEL AND MINES to pleased to state :

(a) whether he is aware that because of supply of the low quality of coking coal the machineries in Durgapur Steel Plant were getting damaged and the production capacity of blast fournances is also going down; and

(b) if so, what steps Government have taken against the management who are responsible for damaging the national property?

THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL & MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE) (a) & (b) Government is aware that the poor quality of coking coal supplied to the Durgapur Steel Plant (DSP) is one of the contributory factors leading to the loss of production and poor performance of the blast furnaces. No damage to equipment has, however, been reported on this account.

Steps have been/are being taken to remedy the situation. It has been impressed upon the coal producing agencies to control the ash control with a view to improving the quality of coking coal to the desired level. Efforts are also being made by D.S.P. to intensify washing of the raw coal at its captive washery to achieve higher ash drops than designed. Besides, coke cutting scheme has been undertaken to economise on the use of coke and to improve the blast furnace productivity.

तम्बाकू से प्राप्त होने वाला वार्षिक राजस्व

1654. श्री छोतू भाई गामितः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा तम्बाकू से प्राप्त होने वाले वार्षिक राजस्व का सर्वेक्षण किया गया है ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा वपा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सथाई सिंह सिसोदिया) : (क) श्रौर (ख) ग्रनिर्मित तम्बाकू को 1 मार्च 1979 से उत्पादन शुल्क से छूट मिली हुई है। वर्ष 1980-81 के लिए निर्मित तम्बाकू के विभिन्न उत्पादों से प्राप्त होने वाले राजस्व सम्बन्धी बजट-ग्रनुमान नीचे दिये गये हैं :---

उत्पादन का नाम	राजस्व
	(करोड़ रुपयों में)
सिगार ग्रौर चुरुट	0.04
सिगरेट	639.96
बीड़ियां	113.42
धुम्रपान मिश्रण	1.29
खैनी तम्बाकू	20.79
नसवार	5.15
हुक्का तम्बाकू	0.46